



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

छत्तीसगढ़ राज्य में ई-प्रशासन

डॉ. संजय कुमार यादव

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)

शासकीय महाविद्यालय करतला

जिला – कोरबा (छ. ग .)

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य 1990 और 2000 के दशक के मध्य में शुरू हुई और वर्ष 2000 में ही छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। दो दशक में यह अपेक्षाकृत नया राज्य ई-गवर्नेंस और सरकारी कामकाज को आसान बनाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामले में मजबूती से आगे बढ़ा है। इस अभियान का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक पहुंचना है और उन्हें कम्प्यूटरीकृत सेवा प्रदान करना है , जो नागरिकों को सक्षम कर सकते हैं और उन्हें बड़ा लाभ दिला सकते हैं।

की वर्ड - ई-प्रशासन, नागरिक ,ई-सेवाओं, स्वागतम पोर्टल, ई- डिस्ट्रिक्ट ,

ई-गवर्नेंस की विभिन्न धारणाएँ -

- ई-प्रशासन और ई-सेवाओं का एक साथ समायोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई-सरकार कहा जाता है।
- ई-गवर्नेंस समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इसमें नागरिकों के लिये नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल है।
- ई-लोकतंत्र राज्य के शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आईटी का उपयोग शामिल है। इसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेहिता और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।

भारत ई-गवर्नेंस की दिशा में कदम -

- 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई-गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था क्योंकि इसमें 'सूचना' और 'संचार' पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिये "जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम" शुरू किया।
- ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च **NICNET** (राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क) एक क्रांतिकारी कदम था।
- डिजिटल इंडिया पहल इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**Meity**) द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

ई-गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार -

- **G2G** यानी सरकार से सरकार
- **G2C** यानी सरकार से नागरिक
- **G2B** यानी सरकार से व्यापार
- **G2E** यानी सरकार से कर्मचारी

ई-गवर्नेंस के उदय के कारण -

- शासन का जटिल होना
- सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि

ई-गवर्नेंस के उद्देश्य -

परियोजना के व्यापक उद्देश्यों में शामिल हैं -

- जिला प्रशासन और उसके अधीनस्थ कार्यालयों की आंतरिक प्रक्रियाओं को आईटी सक्षम बनाकर कार्यात्मक दक्षता में वृद्धि करना।
- नागरिकों के आसपास के क्षेत्र में सरकार से नागरिक तक (जी2सी) सेवाओं को नागरिकों को आसानी से सुविधा उपलब्ध कराना तथा सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना।

- सीएससी/ ई-मित्र किओस्क के जैसे वितरण वाहिका के माध्यम से कुशल व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करना।
- जिला प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कृत्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन आसान करने के लिए और पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन और दक्षता में सुधार करना।
- विभिन्न जिलों के आधारभूत आँकड़े को एकीकृत करके नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय करना।
- ई-जिला परियोजना और अन्य सेवाओं के लिए आईटी अवसंरचना का सृजन करना।
- आईटी सक्षम व्यवस्था और अनुप्रयोगों के निश्चय के साथ परिचालन के लिए सरकारी एजेंसियों/विभागों की मानव संसाधन क्षमता का विकास करने व नागरिकों को सहज व कुशलतापूर्वक सेवाएं उपलब्ध कराना।

ई-गवर्नेंस के लाभ -

- ई-गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। इससे जनता और सरकार के बीच स्वस्थ एवं पारदर्शी संवाद को मजबूत बनाया जा सकता है।
- ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार को सारे आँकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सरकारें विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ बनाने के दौरान इन आँकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय ले सकती हैं।
- सुशासन के लिये एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाकर तीव्र किया जा सके और यह ई-गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव है।
- ई-गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ है।
- कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों की वजह से तेज़ी से अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं।

ई गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियाँ -

- अवसंरचना - बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
- लागत - ई-गवर्नेंस हेतु किये जाने वाले उपकरण उपाय महँगे होते हैं और इनके लिये भारी सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में, ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में परियोजनाओं की लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है।
- गोपनीयता और सुरक्षा - डेटा लीक होने के मामलों ने ई-गवर्नेंस के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल दिया है। इसलिये, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सभी वर्गों के लोगों के हितों

की सुरक्षा के लिये सुरक्षा मानक और प्रोटोकॉल होने चाहिये नवम्बर 2023 में 81.5 करोड़ से अधिक लोगो के डाटा लीक होने की पुष्टि हुई थी। अमेरिका स्थित साइबरसिक्योरिटी फर्म रीसिक्योरिटी ने बताया कि यह भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी डेटा चोरी में से एक हो सकती है, क्योंकि 81.5 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों का विवरण डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, बिक्री के लिए उपलब्ध डेटा सेट में आधार और पासपोर्ट विवरण के साथ-साथ नाम, फोन नंबर और पते जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

- जागरूकता की कमी - ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने वाले और इन सेवाओं से वंचित लोगों की संख्या के मध्य बहुत अधिक अंतराल है। यह अंतराल अमीर-गरीब, पुरुष-महिला, शहरी-ग्रामीण आदि क्षेत्रों में देखा जाता है, इस अंतर को कम करने की आवश्यकता है, तभी ई-गवर्नेंस के लाभों का समान रूप से उपयोग किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ में ई-प्रशासन -

छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत नया राज्य होने के बावजूद अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में डिजिटल अर्थव्यवस्था का बेहतर बुनियादी ढांचा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान लोगों के लिए मुख्यमंत्री संचालित बोर्ड पोर्टल सहित 16 से अधिक प्रीमियम डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की थी। खास तौर पर छात्रों को मुफ्त तेज़ इंटरनेट सुविधा की गारंटी देने के लिए वाई-फाई सिटी योजना, सार्वजनिक रूप से ई-क्षेत्र सेवाओं के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, सामाजिक सुरक्षा विभाग की पांच और राजस्व विभाग की छह वार्षिकी योजनाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा, समन्वित छत्तीसगढ़ मोबाइल एप्लीकेशन, छत्तीसगढ़ ग्राउंड्स एसोसिएट गेटवे, लोक सेवा केंद्र और शहरों में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू की गई सेवाओं में से थे। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक और बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPs), राज्य में आईटी विकास और आईटी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल संगठन है।

ई-गवर्नेंस मॉडल -

राज्य में ई-गवर्नेंस मॉडल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना के तहत बजट का प्रावधान किया गया है। आईटी विभाग के बजट में जरूरी उपकरण और मॉडर्न सॉफ्टवेयर आदि के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई-गवर्नेंस के तहत राज्य के 168 नगरीय निकायों में बजट और अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग अटल डैशबोर्ड के जरिए की जाएगी।

गांव-गांव तक इंटरनेट -

भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है। इसके रख रखाव और संचालन के लिए 66 करोड़ रुपये की पूल निधि का गठन किया गया है।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में **WiFi** के जरिए हॉट-स्पॉट स्थापित कर पूरे राज्य में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के अलग-अलग विभागों की तरफ से इस्तेमाल होने वाले ई-परिसंपत्ति, मोबाईल ऐप और वेबसाइट की सायबर सुरक्षा के लिए जरूरी जांच और सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी की जायेगी।

नवीन पहल -

छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और शासकीय काम-काज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में आईटी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीन पोर्टलों ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम किया जा सके।

छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा -

छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सेवा प्रदान की जा रही है -

क्र	कार्य का नाम	प्रकार	समय
1.	Sericulture & aid under Mulberry plantation	CERTIFICATE	15 Day
2.	औजार उपकरण/कर्मशाला निर्माण अनुदान स्वीकृत करवाने हेतु	OTHERS	15 Day
3.	स्वयं सहायता समूहों / सहकारी समितियों का पंजीकरण	SOCIAL WELFARE AND PENSION	15 Day
4.	हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों का पंजीयन	OTHERS	15 Day
5.	राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने बाबत आवेदन पत्र	CERTIFICATE	15 Day
6.	शिल्पकार के पंजीकरण के लिए आवेदन	OTHERS	30 Day
7.	Handicraft&Application for joining Janshree Group Insurance	OTHERS	15 Day
8.	शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र	OTHERS	30 Day
9.	बुनकर के लिए वित्तीय सहायता	OTHERS	15 Day
10.	महिला और बाल विकास	SOCIAL WELFARE AND PENSION	15 Day
11.	जनशक्ति – स्थानांतरण प्रमाणपत्र जनशक्ति ट्रेनिंग के लिए	PERMISSION	7 Day
12.	जनशक्ति – स्थानांतरण प्रमाणपत्र जनशक्ति ट्रेनिंग नियोग्यता के लिए	PERMISSION	7 Day
13.	जनशक्ति –अंक सूची जनशक्ति ट्रेनिंग	OTHERS	15 Day
14.	अंक सूची जनशक्ति ट्रेनिंग नियोग्यता के लिए	OTHERS	15 Day

15.	स्थानांतरण और चरित्र प्रमाणपत्र सरकारी इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक कॉलेज	PERMISSION	3 Day
16.	शाखा परिवर्तन सरकारी इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए	PERMISSION	15 Day
17.	संस्था परिवर्तन सरकारी इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए	PERMISSION	30 Day
18.	शुल्क वापसी सरकारी इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए	PERMISSION	15 Day
19.	शुल्क वापसी सरकारी इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निक कॉलेज दिव्यांगजन	PERMISSION	7 Day
20.	शिकायत सरकारी इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक कॉलेज दिव्यांग जन के लिए	PERMISSION	7 Day
21.	स्थानांतरण और चरित्र प्रमाण पत्र सरकारी इंजीनियरिंग/ पॉलीटेक्निक कॉलेज	PERMISSION	7 Day
22.	ऋण के लिए आवेदन (नए तालाब निर्माण में मत्स्यपालन के लिए)	LICENSE AND PERMIT	30 Day
23.	रॉयल्टी आधार पर जलाशय/तालाब का आवंटन	LICENSE AND PERMIT	7 Day
24.	मत्स्य पालन प्रशिक्षण	LICENSE AND PERMIT	30 Day
25.	मत्स्य पालन बीमा	LICENSE AND PERMIT	15 Day
26.	लीज पर जलाशय/ तालाब का आवंटन	LICENSE AND PERMIT	30 Day
27.	पशु रोग	OTHERS	2 Day
28.	पानी शुद्ध करें	OTHERS	7 Day
29.	Culture & Request for record copy UPLOAD		15 Day
30.	खाद्यान्न पंजीकरण (स्माल कॉटेज हेतु पंजीकरण)	LICENSE AND PERMIT	15 Day
31.	इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना	SOCIAL WELFARE AND PENSION	60 Day
32.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	SOCIAL WELFARE AND PENSION	60 Day
33.	सुखद सहारा योजना के लिए आवेदन	SOCIAL WELFARE AND PENSION	60 Day
34.	विधवा पेंशन योजना	SOCIAL WELFARE AND PENSION	
35.	इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना	SOCIAL WELFARE AND PENSION	60 Day
36.	चॉइस जन्म सुधार	CERTIFICATE	7 Day
37.	चॉइस मृत्यु सुधार	CERTIFICATE	7 Day
38.	चॉइस विवाह प्रमाण पत्र सुधार	CERTIFICATE	15 Day
39.	जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	CERTIFICATE	7 Day
40.	मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	CERTIFICATE	7 Day
41.	सफाई व्यवस्था	URBAN DEVELOPMENT INCLUDING MUNICIPALITY SERVICES	7 Day
42.	स्ट्रीट लाइट बल्ब बदलना	OTHERS	7 Day
43.	अंक सूची प्रतिलिपि सरकारी स्कूल के लिए	OTHERS	15 Day
44.	शुल्क वापसी सरकारी हाई स्कूल के लिए	UTILITY AND BILL PAYMENT	15 Day

45.	स्थानांतरण प्रमाणपत्र सरकारी हाई स्कूल के लिए	PERMISSION	7 Day
46.	चरित्र प्रमाणपत्र सरकारी उच्च माध्यमिकके लिए	PERMISSION	7 Day
47.	अंक सूची हाई स्कूल	OTHERS	15 Day
48.	स्थानांतरण प्रमाणपत्र सरकारी स्कूल के लिए	CERTIFICATE	15 Day
49.	बेरोजगार इंजीनियर	EMPLOYMENT	14 Day
50.	भूमि उपयोग की जानकारी	URBAN DEVELOPMENT INCLUDING MUNICIPALITY SERVICES	30 Day
51.	सूचना का अधिकार नगर निगम/पालिका/पंचायत	RTI	30 Day
52.	जन शिकायत नगर निगम/पालिका/पंचायत	GRIEVANCE	30 Day
53.	जन शिकायत कलेक्टर	GRIEVANCE	30 Day
54.	राशन कार्ड जारी कराने हेतु आवेदन	PDS RATION	30 Day
55.	विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	CERTIFICATE	15 Day
56.	नल कनेक्शन हेतु	URBAN DEVELOPMENT INCLUDING MUNICIPALITY SERVICES	30 Day
57.	संपत्ति नामांतरण नगर पालिका क्षेत्र	URBAN DEVELOPMENT INCLUDING MUNICIPALITY SERVICES	30 Day
58.	होटल व्यापार अनुज्ञप्ति	LICENSE AND PERMIT	15 Day
59.	Ayush & Permanent Registration Form	LICENSE AND PERMIT	3Week
60.	अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन	CERTIFICATE	21 Day
61.	अतिरिक्त योग्यता पंजीकरण के लिए आवेदन	CERTIFICATE	15 Day
62.	दुकान एवं स्थापना पंजीयन हेतु	LICENSE AND PERMIT	15 Day
63.	कीटनाशक लाइसेंस	LICENSE AND PERMIT	30 Week
64.	Horticulture & New Seed License	LICENSE AND PERMIT	30 Day
65.	सीड व्यापार	PERMISSION	10 Day
66.	सीड प्रसंस्करण	PERMISSION	15 Day
67.	Agriculture&Fertilizer License	LICENSE AND PERMIT	30 Week
68.	बीज लाइसेंस का नवीकरण	LICENSE AND PERMIT	30 Day
69.	नए किस्म के बीज लाइसेंस को शामिल करना	LICENSE AND PERMIT	30 Day
70.	Agriculture&Equipment	PERMISSION	10 Day
71.	नया बिजली कनेक्शन	LICENSE AND PERMIT	12 Day
72.	Forest &Registration of Wood	CERTIFICATE	30 Day
73.	स्थापित सॉ मिल को चलाने के लिए मंजूरी लाइसेंस के लिए आवेदन	LICENSE AND PERMIT	30 Day
74.	वन उत्पाद के लिए खुदरा बिक्री की मंजूरी के लिए आवेदन	LICENSE AND PERMIT	30 Day

75.	वन विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र	CERTIFICATE	45 Day
76.	संघ / संस्थानों और खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता	REVENUE	15 Day
77.	मूल निवासी प्रमाण पत्र	CERTIFICATE	15 Day
78.	आय प्रमाण पत्र	CERTIFICATE	15 Day
79.	सूचना का अधिकार जिला कलेक्टर	RTI	30 Day
80.	प्रकरण सूची (राजस्व न्यायालय)	REVENUE COURT	7 Day
81.	न्यायालय आदेश प्रमाण पत्र (राजस्व न्यायालय)	REVENUE COURT	15 Day
82.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र	CERTIFICATE	30 Day
83.	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र	CERTIFICATE	30 Day
84.	लॉकडाउन से छुट का आवेदन पत्र (वैवाहिक कार्यक्रम हेतु)	REVENUE	3 Day
85.	कैदी से मिलने का अनुरोध		15 Day
86.	स्थायी फटाका लाइसेंस	CERTIFICATE	30 Day
87.	अस्थायी फटाका लाइसेंस	CERTIFICATE	21 Day
88.	पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु एन ओ सी	CERTIFICATE	75 Day
89.	सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत सिनेमा लाइसेंस	CERTIFICATE	75 Day
90.	विस्फोटक सामग्री विक्रय ,परिवहन एवं निर्माण हेतु एन ओ सी	CERTIFICATE	75 Day

- e District पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार

सुझाव -

- ग्रामीण क्षेत्रों में ई-शासन की पहल ज़मीनी हकीकत की पहचान और विश्लेषण करके की जानी चाहिये।
- सरकार को विभिन्न हितधारकों अर्थात नौकरशाहों, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों, आदि के लिये उचित, व्यवहार्य, विशिष्ट और प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- ई-गवर्नेंस से संबंधित सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बड़ी भूमिका है। क्लाउड कंप्यूटिंग न केवल लागत में कमी लाने का एक उपकरण है, बल्कि नई सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम होने के साथ ही शिक्षा प्रणाली में सुधार और नई नौकरियों / अवसरों के सृजन में भी मदद करता है।
- क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई-गवर्नेंस भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिये अत्यंत प्रासंगिक है।

निष्कर्ष -

ई-जिला परियोजना का उद्देश्य जिला प्रशासन और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए एक एकीकृत आईटी मंच तैयार करना है जिसका उद्देश्य आईटी का उपयोग मुख्य रूप से सूचना की गुणवत्ता में वृद्धि, समग्र रूप से सरकारी प्रक्रिया में दक्षता के साथ-साथ संचालन में सुविधा भी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के डिजिटल परिदृश्य में विकसित होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस पहल के कार्यान्वयन से छत्तीसगढ़ के डिजिटल परिवर्तन में मदद मिलेगी और यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, बैंकिंग और अन्य कई क्षेत्रों में सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होगा।

सन्दर्भ -

- 1 डिजिटल इंडिया के लिए साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है ऑनलाइन <http://www.firstpost.com/business/why-cyber-security-is-important-for-digital-india-2424380.html> एक्सेस किया गया,.
- 2 डिजिटल इंडिया पावर ऑफ एम्पावर ऑनलाइन,, www.digitalindia.gov.in एक्सेस किया गया,।
- 3 वैश्विक सूचकांक के अंतर्गत ई-सरकार विकास सूचकांक (ईजीडीआई) ऑनलाइन,, : <https://www.meity.gov.in/e-government-development-index-egdi-under-global-indices> एक्सेस किया गया।
- 4 डिजिटलाइजिंग इंडिया एक महत्वपूर्ण शक्ति ऑनलाइन,, 2023. उपलब्ध : https://www.ey.com/en_in/india-at-100/digitalizing-india-a-force-to-reckon-with एक्सेस किया गया,।
- 5 जे. दशोरा, डिजिटल इंडिया सीमाएं और अवसर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एंड इनोवेटिव आइडियाज इन एजुकेशन।
- 6 जी. नीरू और ए. किरणदीप, डिजिटल इंडिया ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक रोडमैप। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट।